this context I would like to ask the hon. Minister or the Prime Minister whether the Government has made any effort to export automobile parts. If so, to which country and what was its volume in terms of dollars and rupees during the year 1992-93?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pending cases in Supreme Court relating to reservation of SC/STs

*422. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of cases relating to reservation of SC/STs pending in Supreme Court, as on 1-8-1993, for more than one year, for more than five years, for more than ten years and for more than fifteen years, separately;

(b) whether the Supreme Court proposes to constitute a special bench for deciding all the matters relating to reservation of SC/STs within a limited period keeping in view the Government policy; and

(c) the total number of Government counsels at present for Supreme Court working on behalf of Central Government and number of SC/STs therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) As per the information made available by the Registry of the Supreme Court, 83 cases relating to reservation of SCs/STs were pending as on 1st August, 1993. The break-up is as follows:

More than 1 year	—	83 cases
More than 5 years	—	80 cases
More than 10 years	—	63 cases
More than 15 years	—	1 case

(b) The above matters are already before the Constitution Bench of the Supreme Court.

(c) Of the 10 full time Advocates working for the Government in the Supreme Court, one belongs to SC category.

गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाया जाना

*426. श्री रामसिंह राठवा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनकी सेवाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये इन स्वैच्छिक संगठनों के पूर्व कार्यों की समीक्षा की है कि कहीं इन संगठनों के विरुद्ध विगत में सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें तो नहीं की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास) में राज्य मंत्री (श्री कमल राम सिंह): (क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत गुजरात सहित देश में बंजर भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, बंजर भूमि के विकास के लिए सहायता चाहनेवाले स्वैच्छिक संगठन अपनी ओर से राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को आवेदनपत्र देते हैं और अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें गुजरात के संगठन भी शामिल हैं, से अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों की टिप्पणी प्राप्त कर लेने के बाद अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन की भी व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संगठनों को रिलीज की गई धनराशि का समुचित ढंग से उपयोग किया गया है।

Ban on Benzidine and Benzidine-based Dyes

*427. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the manufacture, marketing and use of Benzidine and Benzidine-based dyes were banned with effect from January 31, 1993 on account of their carcinogenic nature;

(b) whether it is also a fact that despite the Government giving more than three years time before imposing the ban to the manufacturers and users, Benzidine-based dues continue to be manufactured, sold and used even after the ban has become effective; and

(c) if so, what steps Government have taken to enforce the ban in right earnest; and what steps are further contemplated to enforce the ban?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) As per information received from the Ministry of Environment & Forests, the manufacture and use of Benzidine-based dyes were banned with effect from the 30th January, 1993 on account of their carcinogenic nature.

(b) and (c) The Ministry of Environment & Forests is ascertaining the detailed position in this regard.

कुटीर उद्योगों की स्थापना

*428. **श्री राम जेठमलानी**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का यह विचार है कि देश से कपास के निर्यात पर रोक लगाकर देश के ग्रामों में कपास से सूत बनाने के लिए भारी संख्या में कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयोग द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूत की कताई के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या आयोग सूत-कताई उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनायेगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एच. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सरकार ने सूत की कताई के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों में हमेशा मदद की है ।

(च) आयोग ने सूत-कताई उद्योग को बढ़ावा देने की कई योजनाएं तैयार की हैं । यह एक सतत प्रक्रिया है ।

Recovery from Drug Companies

429. DR. NARREDDY THULASI REDDY :
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 80 given in Rajya Sabha on 29th April, 1993, and state :

(a) what are the names of 29 companies from whom Rs. 17.89 crores was recovered and what are the names of drugs/formulations against which amount has been recovered;

(b) what is the total amount due from each of these 29 companies and how much was recovered from each and what are the details of basis on which such a recovery was made;

(c) what are the details of stays in each case and what initiative has been taken by Government to get the stays vacated;

(d) whether it is a fact that Government have set up a new cell to expedite the recovery; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (c) The details asked for, are contained in the Statement I and Statement II respectively.

(d) and (e) No Sir.

Statement I

Details of amount recovered from Drug Companies into DPEA

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the Company (Drugs involved)	Period involved	Tentative Assessment	Amount Received
1	2	3	4	5
1.	M/s Cyanamid (I) Ltd. (Dimethylchloro Tetracycline & formulations)	Upto Dec., 83 1984—87	490.47 830.05 1320.52	100.00